एलपीजी पर वृद्धि को वापस ले केंद्र सरकार

अपील

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

सर्वोच्च हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की लागत में असामान्य वृद्धि से आतिथ्य उद्योग को तत्काल राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है।

एक ज्ञापन के जरिये एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि स्टैंडअलोन रेस्तरां को आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस पर लगने वाले कर की दर को मौजूदा 18 से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए। एफएचआरएआई ने कहा कि चूंकि स्टैंडअलोन रेस्तरां को आईटीसी का दावा करने की अनुमति नहीं है, इसलिए इस कदम से रेस्तरां पर लागत का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

नवीनतम मूल्य वृद्धि 1 जनवरी 2014 के बाद एलपीजी में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है, जब 19 किलो का सिलेंडर 353.50 रुपये (दिल्ली में) महंगा हो गया था। रेस्तरां, विशेष रूप से स्टैंडअलोन रेस्तरां लागत में अब इतनी भारी वृद्धि को सहन नहीं

मांग

- आतिथ्य उद्योग को तत्काल राहत प्रदान करने का अनुरोध
- कर की दर मौजूदा 18 फीसदी घटाकर पांच प्रतिशत की जाए

कर सकता है। एफएचआरएआई ने कहा है कि एलपीजी रेस्तरां उद्योग में सबसे आवश्यक वस्तुओं में से एक है, कीमतों में भारी वृद्धि देश के सभी हिस्सों के सैकड़ों छोटे रेस्तरां के लिए एक बड़ी समस्या है।

एफएचआरएआई के उपाध्यक्ष गुरबक्षीश सिंह कोहली ने कहा, डीजल की लागत में भारी वृद्धि ने रसद शुल्क में भारी वृद्धि की है जिसके कारण अनाज, दाल, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक कच्चे माल की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है। लॉकडाउन अवधि के बाद से रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की लागत में 30 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है।